केंद्रीय खनन योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड

बनाम

रामू पासी और अन्य

8 दिसंबर, 2005

(अरिजीत पसायत और तरुण चटर्जी, जे.जे.)

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923:

धारा 2 (एन) "कर्मचारी"-आयोजित, एक आकस्मिक कर्मचारी को शामिल नहीं करता है-इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दावेदार को नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नियुक्त किया गया था-श्रम न्यायालय के समक्ष दावा याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी-हालाँकि, दी गई छोटी राशि पर विचार करते हुए, राशि, यदि पहले से ही भुगतान की गई है, तो बरामद नहीं की जाएगी-यदि दावेदार को धन का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे तुरंत भुगतान किया जाएगा।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:

सिविल अपील सं. 979/2000

1992 (आर) के एम.ए. सं. 153 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.1.98 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी.ए. सं. 980/2000

अपीलार्थी के लिए अनीप सचदे।

उत्तरदाताओं के लिए सुश्री के. शारदा देवी।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अरिजीत पासायत, जे.

ये दोनों अपीलें श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत रामू पासी (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा किए गए दावे से संबंधित हैं। उक्त रामू पासी द्वारा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने वाले दावे का न्यायनिर्णय करते हुए, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धनबाद (संक्षेप में 'श्रम न्यायालय') ने दिनांक 11.06.1986 को 4001 हजार रुपये के मुआवजे का आदेश दिया। दावेदार के अनुसार, बाईं अनामिका उंगली पर चोट तब लगी जब वह अपीलार्थी के कारखाने में काम

कर रहा था। धारा 30 के तहत पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी।

ये दो अपीलें रामू पासी द्वारा किए गए दावे से संबंधित हैं यह रुख अपनाते हुए कि अधिनियम की धारा 2 (एन) में परिभाषित 'कामगार', ए अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आते हैं और इसलिए श्रम न्यायालय के समक्ष उनकी दावा याचिका विचारणीय नहीं थी। चूंकि, श्रम न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि आवेदक रामू पासी एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, इसलिए उसे दावा याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा, कर्मचारी को नियोक्ता के व्यापार और व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि उक्त प्रश्न वास्तव में एक शैक्षणिक हित का था क्योंकि प्रदान की गई राशि बहुत कम थी। डिवीजन बेंच के समक्ष एक लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी गई, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह विचारणीय नहीं था। इन अपीलों में, विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेश पर हमला किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने के बाद कि दावेदार एक आकस्मिक कर्मचारी था, अधिनियम के तहत मुआवजे के अनुदान के लिए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, विद्वान न्यायमित्र सुश्री के. शारदा देवी ने कहा कि कम मात्रा को देखते हुए, यह हमारे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। इसके अलावा श्रम न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति पर विचार करते हुए दावा याचिका पर विचार किया।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, अधिनियम की धारा 2 (एन) पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर था। उस समय अधिनियम की धारा 2 (एन) इस प्रकार थीः

"धारा 2 (एन)" "कर्मचारी" "से कोई भी व्यक्ति (उस व्यक्ति के अलावा जिसका रोजगार आकस्मिक प्रकृति का है और जो नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्यों के अलावा अन्य रूप से नियोजित है) अभिप्रेत है जो-"

(i) भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 (9 का 1890) की धारा 3 में परिभाषित एक रेलवे कर्मचारी, जो रेलवे के किसी भी प्रशासनिक,

जिले या उप-मंडल कार्यालय में स्थायी रूप से कार्यरत नहीं है और अनुसूची II में निर्दिष्ट किसी भी क्षमता में कार्यरत नहीं है, या

(ii) अनुसूची II में निर्दिष्ट किसी भी क्षमता में मासिक मजदूरी (एक हजार रुपये) से अधिक नहीं पर नियोजित।

चाहे रोजगार का अनुबंध इस अधिनियम के पारित होने से पहले या बाद में किया गया था और क्या ऐसा अनुबंध मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त किया गया है या निहित है, लेकिन इसमें (संघ के सशस्त्र बलों) के सदस्य के रूप में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है और किसी ऐसे कर्मचारी का कोई संदर्भ जो घायल हो गया है, जहां कर्मचारी की मृत्यु में उसके आश्रितों या उनमें से किसी का संदर्भ शामिल है।

उक्त अधिनियम को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि अधिनियम में परिभाषित 'कामगार' अभिव्यक्ति एक आकस्मिक कर्मचारी को शामिल नहीं करती है। यह दिखाने के लिए कोई निश्चित सामग्री भी प्रस्तुत नहीं की गई थी कि दावेदार को नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नियोजित किया गया था।

ऐसा होने के कारण, श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन स्पष्ट रूप से विचारणीय नहीं था। उस हद तक, श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने विचार में सही नहीं थे। लेकिन दी गई छोटी राशि पर विचार करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि राशि, यदि पहले से ही दावेदार को भुगतान किया जा चुका है, तो उसकी वसूली नहीं की जाएगी। यदि दावेदार को धन का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे तुरंत भुगतान किया जाएगा।

यदि यह जमा पर है, तो दावेदार द्वारा इसे निकालने की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

आर.पी.

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।